

भारतीय संदर्भ में वैश्वीकरण और अर्थव्यवस्था

डॉ. दीपक पंचोली – असिस्टेंट प्रोफेसर, एस.एम.सी.जी.एम.टी.टी. कॉलेज, आबूरोड़

सारांश : आधुनिक समय में वैश्वीकरण को एक नवीन अवधारणा के रूप में स्वीकार किया जाता है। वैश्वीकरण से तात्पर्य विश्व स्तरीय प्रक्रियाओं से हैं। किसी भी विषय का वैश्विक संदर्भ में प्रयोग उस विषय विशेष का वैश्वीकरण कहलाता है। भारतीय सन्दर्भ में यदि वैश्वीकरण के महत्व की बात की जाये तो इसके दोनों पहलू अर्थात् सकारात्मक एवं नकारात्मक, दृष्टिगत होते हैं। आर्थिक आधार पर भारत के लिए वैश्वीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए खोलता है। इससे भारत सहित अन्य राष्ट्रों की परस्पर निर्भरता में वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण विश्व के राष्ट्रों में विदेशी पूंजी के प्रवाह में तेजी से वृद्धि करता है। विदेशी पूंजी का प्रवाह प्रत्यक्ष निवेश एवं पोर्टफोलियों के रूप में गतिमान होता है। विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय महत्व के कई उद्योगों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 51: कर दी गई है।

वैश्वीकरण के कारण भारत जैसे विकासशील देश में निर्धनता में कमी आई है। एशियन विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी 1977-78 में 51: से घटकर वर्ष 1999-2000 में 26: हो गई है और यह गिरावट अभी भी जारी है। वैश्वीकरण के द्वारा भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संभव होने से भारत की पूंजी की समस्या का समाधान होता जा रहा है तथा ऋणग्रस्तता में कमी आयी। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप भारत सहित अधिकांश राष्ट्रों द्वारा उदारीकरण को प्रोत्साहन दिया गया जिसने भारतीय औद्योगिक, व्यापारिक, वित्तीय और आर्थिक व्यवस्था को गहनता से प्रभावित किया है। आर्थिक क्षेत्र में जहाँ अधिकांश सकारात्मक प्रभाव प्राप्त हुए वही सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में समन्वित प्रभाव दृष्टिगत हुए हैं।

विषय प्रवेश : आधुनिक समय में वैश्वीकरण को एक नवीन अवधारणा के रूप में स्वीकार किया जाता है। वैश्वीकरण से तात्पर्य विश्व स्तरीय प्रक्रियाओं से हैं। किसी भी विषय का वैश्विक संदर्भ में प्रयोग उस विषय विशेष का वैश्वीकरण कहलाता है।

आधुनिक समय में राष्ट्रीयकरण एक संकीर्ण विचारधारा मानी जाती है क्योंकि वर्तमान समय में कोई भी देश सम्पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है एवं अन्य वैश्विक देशों की समस्याएँ एवं गतिविधियाँ एक-दूसरे को प्रभावित करती हैं। पूर्व के दो विश्वयुद्धों की विभीषिकाओं से सबक लेते हुए सभी राष्ट्र भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति से बचना चाहते हैं। इस हेतु वैश्विक शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो विश्व को युद्धों से बचाकर आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उन्नति का पथ प्रशस्त कर सकती है।

वैश्वीकरण : वैश्वीकरण आर्थिक क्षेत्र में एक नवीन क्रांति है जिसके अन्तर्गत विश्व आर्थिक नीति को एक केन्द्रिय बिन्दु से नियमित, नियंत्रित एवं संचालित करने का प्रयास है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत किसी भी राष्ट्र के व्यापार सम्बन्धी आयात एवं निर्यात को एकीकृत एवं समन्वित करके उसे अन्तरराष्ट्रीय बाजार की शक्तियों पर मुक्त छोड़ दिया जाता है।

आर्थिक संदर्भ में वैश्वीकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा दुनियाँ की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को समन्वित किया जाता है जिससे वस्तुओं और सेवाओं, तकनीकों, पूंजी तथा श्रम का इनके मध्य प्रवाह हो सके अर्थात् घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ाव।

एन. वाधुल के अनुसार, "वैश्वीकरण शब्द बाजार क्षेत्र के तीव्र विस्तार को प्रकट करता है जो विश्वव्यापी पहुँच रखता है।"

भारत में वैश्वीकरण की आवश्यकता : भारतीय सन्दर्भ में यदि वैश्वीकरण के महत्व की बात की जाये तो इसके दोनों पहलू अर्थात् सकारात्मक एवं नकारात्मक, दृष्टिगत होते हैं। वैश्वीकरण ने जहाँ भारतीय संस्कृति को गहनता से दुषित किया है वहीं दूसरी ओर इससे देश के जीवन को नई उर्जा प्राप्त हुई है। पुरानी, कुँ की मेंढक वाली मानसिकता को त्याग कर भारत सहित सभी राष्ट्रों की सोच व्यापक बनी है एवं राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण भी अन्तर्राष्ट्रीय सन्दर्भ में किया जाने लगा है। किसी भी राष्ट्र में मानवीय आपदा हो या प्राकृतिक आपदा, विश्व के अन्य राष्ट्र परस्पर सहयोग हेतु तत्पर रहते हैं।

आर्थिक आधार पर भारत के लिए वैश्वीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए खोलता है। इससे भारत सहित अन्य राष्ट्रों की पर परस्पर निर्भरता में वृद्धि हुई है।

वैश्वीकरण और विदेशी निवेश : वैश्वीकरण में विश्व का विकास एकल एकीकृत आर्थिक इकाई के रूप में होता है और बाजार के रूप में केवल विश्व बाजार का अस्तित्व होता है। इस प्रकार की स्थिति में प्रतिस्पर्धा के आधार पर मुक्त व्यापार की सीमा रेखा विहीन सत्ता की ओर सभी देश अग्रसर होते हैं।

वैश्वीकरण के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रमुख तत्व समाहित है –

1. सभी राष्ट्रों द्वारा आयात शुल्क घटाना।
2. आयात नीति को अधिक उदार बनाना तथा आयात पर प्रतिबन्धों में ढील देना।
3. विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना।
4. विदेशी तकनीकी सम्बन्धी सन्धियों को प्रोत्साहन देना।

वैश्वीकरण से विश्व के राष्ट्रों में विदेशी पूंजी का प्रवाह तेजी से वृद्धि करता है। विदेशी पूंजी का प्रवाह प्रत्यक्ष निवेश एवं पोर्टफोलियों के रूप में गतिमान होता है। विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय महत्व के कई उद्योगों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 51% कर दी गई है।

भारत सरकार द्वारा सन् 1996-97 में, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की नीतियों को और अधिक लचीला बनाया गया तथा 9 प्रकार के उद्योगों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 74% तक स्वतः अनुमोदन की आज्ञा दी गई। विदेशी निवेश के प्रस्तावों को शीघ्र अनुमोदित करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन परिषद् की स्थापना की गई है। इन प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप भारत में निजी विदेशी पूंजी का प्रवाह अत्यन्त तीव्रता से बढ़ गया। इसमें भी आधा पोर्टफोलियों निवेश भारतीय स्टॉक मार्केट में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किया गया।

वैश्वीकरण और उत्पाद : वर्तमान समय में प्रत्येक राष्ट्र की प्रगति उसके विदेशी मुद्रा भंडार एवं विदेशी पूंजी पर निर्भर करती है। अतः अन्य देशों के साथ-साथ भारत ने अपनी विदेशी पूंजी बढ़ाने के लिए आर्थिक उदारीकरण का सहयोग लिया। आर्थिक उदारीकरण के परिणामस्वरूप विभिन्न देशों के लिए भारत ने अपना बाजार मुक्त कर दिया फलस्वरूप बाजार में प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ हो गई एवं उपभोक्ताओं के पास उत्पादों के चयन के लिए अनेकों विकल्प उपस्थित होने लगे। चूंकि विकसित राष्ट्रों के पास पर्याप्त पूंजी एवं अत्याधुनिक तकनीकी थी जिसके कारण उनके द्वारा निर्मित माल सस्ता एवं गुणवत्ता पूर्ण था अतः उपभोक्ताओं ने सस्ता एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पादों को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया चाहे वह उत्पाद किसी भी देश का क्यों ना हो। ऐसी परिस्थिति में भारतीय घरेलू उद्योग भारी घाटे के कारण बन्द होने लगे। यद्यपि सरकार इस स्थिति में सुधार हेतु निरन्तर प्रयत्नरत है। परन्तु यह कठिन कार्य है।

वैश्वीकरण और कार्मिक : वैश्वीकरण की प्रक्रिया में पूरी दुनियाँ एक परिवार की तरह हो गई है। सभी प्रकार की सीमाएँ अर्थहीन हो चुकी हैं। वर्तमान युग आर्थिक युग है एवं प्रत्येक व्यक्ति अपनी आर्थिक उन्नति चाहता है। उच्च वेतन, शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक सफलता का एक मापदण्ड बन चुका है। अतः उच्च वेतन की आकांक्षा में युवा वर्ग किसी भी देश में अपनी सेवाएँ देने हेतु तत्पर रहते हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों भी अपने कर्मचारियों को अलग-अलग देशों में नियुक्ति दे देती हैं। इससे श्रमिकों एवं कर्मियों का स्वतन्त्र प्रवाह होता है।

वैश्वीकरण का भारत पर प्रभाव :

1.) सन् 1991 की शुरुआत में भारत को भीषण भुगतान संतुलन के संकट का सामना करना पड़ा था एवं इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए भारत को अपनी औद्योगिक नीति में मूलभूत परिवर्तन करने पड़े जिसमें प्रमुख हैं –

- निजी पूंजी निवेश को स्वतंत्रता प्रदान करना।
- औद्योगिक लाइसेन्स व्यवस्था का अन्त करना।
- अनेक वस्तुओं पर मूल्य नियन्त्रण समाप्त करना।
- लघु उद्योगों के संरक्षण से सम्बन्धित नीतियों में कमी करना।

➤ भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (F.D.I.) और विदेशी व्यापार के लिए खोलना।

उपरोक्त नीतियों में संशोधन के परिणामस्वरूप भारतीय औद्योगिक वातावरण में मूलभूत परिवर्तन हुए। वर्तमान में विकसित देशों की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के दबाव में सभी राष्ट्रों की औद्योगिक नीतियाँ वैश्वीकरण से प्रभावित होती हैं।

2.) वैश्वीकरण के कारण भारत जैसे विकासशील देश में निर्धनता में कमी आई है। एशियन विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी 1977-78 में 51% से घटकर वर्ष 1999-2000 में 26% हो गई है और यह गिरावट अभी भी जारी है।

3.) वैश्वीकरण के द्वारा भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संभव होने से भारत की पूंजी की समस्या का समाधान होता जा रहा है तथा ऋणग्रस्तता में कमी आई है।

4.) प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से भारत में उत्पादन क्षमता एवं संवृद्धि दर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

5.) भारतीय उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर उच्चगुणवत्ता युक्त वस्तुएँ उपलब्ध हो रही हैं। प्रतिस्पर्धा के कारण घरेलू उद्योगों की गुणवत्ता में सुधार आया है।

6.) शिक्षा के क्षेत्र में नई-नई शैक्षिक तकनीकों को समावेशित किया जा रहा है। प्रोजेक्टर, विडियो कान्फ्रेंसिंग के आधार पर प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि आदि का प्रयोग शिक्षा में किया जा रहा है फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में बिना बोझ के शिक्षा, निर्मितवाद, अभिसंज्ञानवाद आदि नये सम्प्रत्यय उभर रहे हैं।

निष्कर्ष : द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् विश्व बैंक व अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना वैश्वीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास थे। डंकल प्रस्ताव के आधार पर विश्व व्यापार संगठन वैश्वीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। डंकल प्रस्ताव के आधार पर विश्व स्तर पर पेटेन्ट नियम लागू करना, बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रवेश को सरल बनाना, विदेशी विनियोग के अन्तर्वाह एवं बहिर्वाह को सरल बनाना आदि पहलुओं पर बल दिया गया।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप भारत सहित अधिकांश राष्ट्रों द्वारा उदारीकरण को प्रोत्साहन दिया गया जिसने भारतीय औद्योगिक, व्यापारिक, वित्तीय और आर्थिक व्यवस्था को गहनता से प्रभावित किया है। आर्थिक क्षेत्र में जहाँ अधिकांश सकारात्मक प्रभाव प्राप्त हुए वही सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में समन्वित प्रभाव दृष्टिगत हुए हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :

1. पाण्डेय, रामशकल(1963), आधुनिक शिक्षा का विकास, मेट्रीपोलिटन बुक कम्पनी (प्रा.) लि., दिल्ली।
2. शर्मा, आर.ए.(2006), भारतीय शिक्षा का विकास, आर.लाल. बुक डिपो, मेरठ।
3. Sharma, V.K.(2004), Comparative Education, Kanishka Publishers, Distributors, New Delhi.
4. Chaube, S.P.(1965), A Survey of educational problems and Experiments in India, Kitab Mahal, Allahabad.
5. Hans, H.(1959), Comparative Education, Rout ledge and Kegan Paul, London.
6. Kandel, I.L. The New Era in Education, Houghton Mifflin Company, The relevant pages.
7. Private Participation in India Higher Education : Contemporary Issues and challenges, (Feb. 16-22, 2004, Vol. 42, No. 07)
8. "Foreign Providers in Indian Higher Education System". (Sep. 13-19, 2010, Vol. 48, No. 37)
9. Hans, H.(1959), Carroy, M.(1999), Globalization and Educational Reform : What Planners Need to know, Report No. 63, International institute of Educational Planning.